RACE IAS

A Leading Institute For Civil Services Examinations

ANSWERS & EXPLANATIONS

GENERAL STUDIES (P) 2024

FULL LENGTH

QUESTIONS BOOKLET NO. : 2320243924

EXAM DATE : 20/04/2024

1. Answer: c
   - Candidates fielded by political parties registered with the Election Commission of India will get preference in the matter of allotment of free symbols over independent candidates.
   - Additionally, political parties may, with the passage of time, seek recognition as 'State Party' or 'National Party' subject to the conditions laid down by the Commission in the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as amended from time to time. Will be subject to completion.
   - If the party is recognized as a 'State Party', it is eligible for exclusive allotment of its reserved symbol to the candidates fielded by it in the 'States' in which it is so recognized and.
   - If the party is recognized as a 'National Party' it shall be entitled to the exclusive allotment of the symbol reserved by the party to the candidates fielded by it throughout the country.

2. Answer: d
   - Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the State towards securing all or any of the principles set out in Part IV shall be void on the ground that it is inconsistent with, or removes Or abbreviates.
   - any of the rights conferred by article 14 or article 19; and no law containing a declaration that it is intended to give effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy:
   - Provided that where such law is made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply to it unless such law, being reserved for the consideration of the President, receives the assent of him.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

1. उत्तर: c
   - भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को निर्दलीय अभ्यर्थियों की तुलना में मुक्त प्रतीकों के आबंटन के मामले में प्राथमिकता मिलेगी।
   - इसके अतिरिक्त , समय बीतने के साथ राजनैतिक दल 'राज्यीय दल' या 'राष्ट्रीय दल' के रूप में मान्यिता प्राप्तं कर सकते हैं परंतु यह समय-समय पर यथासंशोधित, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यआधीन होगा।
   - यदि पार्टी को 'राज्यीय पार्टी' की मान्स्ता मिली हुई है तो यह उन राज्यों , जिसमें उसे इस प्रकार की मान्यता मिली हुई है, के राज्य' में इसके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को इसके आरक्षित प्रतीक के विशिष्टु आबंटन की पात्र है और ।
   - यदि पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त है तो यह पूरे देश में इसके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को पार्टी द्वारा आरक्षित प्रतीक के विशिष्ट आंबटन की पात्र होगी।

2. उत्तर: d
   - अनुच्छेद 13 में निहित किसी भी बात के बावजूद, भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह असंगत है, या हटाता है या संक्षिप्त करता है।
   - अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी; और कोई भी कानून जिसमें यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है:
   - बशर्ते कि जहां ऐसा कानून किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, इस अनुच्छेद के प्रावधान उस पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसा कानून, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होने पर, उनकी सहमति प्राप्त न कर ले।

3. Answer: c
   - Zonal councils are advisory groups made up of states in India. These councils were formed to increase cooperation among the states. Five councils were established in 1956. The North Eastern Zonal Council was established in 1972.

4. Answer: a
   - As a part of the National e-Governance Plan, the e-Courts Mission Mode Project for ICT development of the Indian Judiciary has been implemented since 2007 based on the "National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary". Is going.
   - It aims to transform the judicial system of the country by making the courts ICT enabled and enhancing judicial productivity qualitatively and quantitatively, thereby making the justice delivery system accessible, cost-effective, reliable and transparent.
   - The e-Courts project is being implemented under the joint partnership of the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India and e-Committee, Supreme Court of India in a decentralized manner through the respective High Courts.

5. Answer: C
   - The Swachhita Yojana is a wealth survey program that was launched on April 24, 2020 by Indian Prime Minister Narendra Modi as a central sector scheme to promote socio-economic protection and greater self-esteem.
   - The scheme will involve about 6.62 lakh field surveys across the country from 2021 to 2025, which will involve the use of various technologies to collect property data.
   - The initial phase of this scheme was implemented in selected areas of Maharashtra, Karnataka, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Punjab and Rajasthan during 2020-21.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

3. उत्तर: c
   - आंचलिक परिषद सलाहकार समूहों जो भारत के राज्यों से मिलकर बनी हुई हैं। ये परिषदों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गयी थी। पांच परिषद 1956 में स्थापित हुए थी। पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद 1972 में स्थापित की गयी थी।

4. उत्तर: a
   - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है।
   - इसका उद्देश्य अदालतों को आईसीटी सक्षम बनाकर देश की न्यायिक प्रणाली को बदलना और न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना है, जिससे न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके।
   - ई-कोर्ट परियोजना को संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संयुक्त साझेदारी के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

5. उत्तर: c
   - स्वामित्व वाली योजना एक संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है जो 24 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक-आर्थिक संरक्षण और अधिक आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था।
   - इस योजना में 2021 से 2025 तक देश भर के लगभग 6.62 लाख क्षेत्रीय सर्वेक्षण शामिल होंगे, जिसमें संपत्ति डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल होगा।
   - इस योजना का प्रारंभिक चरण 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा इलाकों में लागू किया गया

6. Answer b
   - Microcredit loan is called micro loan. It is generally given without any collateral. Loans of Rs 1 lakh or less are called micro-loans in India. Generally, to take this you must have a means of earning such as a job or a business.

7. Answer: b
   - The Scheme applies to every establishment employing 20 or more persons, other than excluded employees, and in some cases also to organizations employing less than 20 persons, subject to certain conditions and exceptions.
   - EPFO is the largest social security organization in the world.
   - The Employees' Provident Fund was established with the promulgation of the Employees' Provident Fund Ordinance on 15 November 1951.
   - This Ordinance was replaced by the Employees' Provident Fund Act 1952. The Employees' Provident Fund Bill was introduced in Parliament as Bill No. 15 of the year 1952 to make provisions for the establishment of a provident fund for employees working in factories and other institutions. It is now known as the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952.

8. Answer : a
   - Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) is a central civil services training institute under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India for central civil servants of the Indian Corporate Law Service cadre.

9. Answer d
   - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) implemented by the National Skill Development Corporation (NSDC). This skill certification scheme aims to enable Indian youth to take industry relevant skill training that will help them gain better livelihood.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

6. उत्तर B

लघु-ऋण बहुत छोटे ऋण को कहा जाता है। यह आम तौर पर बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे दिया जाता है। 1 लाख या उससे कम के ऋण को भारत में लघु-ऋण कहा जाता है। सामान्यतः इसे लेने के लिए आपके पास कमाई का साधन होना चाहिए जैसे की कोई नौकरी या कोई व्यवसाय।

7. उत्तर: b

- यह योजना प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें बहिष्कृत कर्मचारियों के अलावा 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और कुछ मामलों में कुछ शर्तों और अपवादों के अधीन 20 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाले संगठन भी इसमें शामिल हैं।
- ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
- कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना दिनांक 15 नवम्बर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई।
- इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया। कर्मचारी भविष्य निधि बिल को संसद में वर्ष 1952 के बिल संख्या 15 के रूप में लाया गया ताकि कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि की स्थापना के प्रावधान हो सके। इसे अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है।

8. उत्तर: a

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) भारतीय कॉरपोरेट लॉ सर्विस कैडर के केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक केंद्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है।

9. उत्तर D

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा

10. Answer d
    - Mission Indradhanush campaign was launched by the Union Health Ministry of the Government of India on 25 December 2014 on the occasion of Good Governance Day to bring all children under vaccination.

11. Answer. d
    - Inactivated polio vaccine (IPV) is the only polio vaccine that has been administered in the United States since 2000. IPV is given by shot in the leg or arm, depending on the age of the patient.
    - Rotavirus vaccine works very well to prevent children from getting infected with rotavirus. It prevents rotavirus infection in 8 out of every 10 babies suffering from rotavirus. Babies get it at 2 and 4 months of age and again at 6 months.
    - Measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine is a combination vaccine that helps protect against these three serious viral infections.

12. Answer b
    - Mother's Complete Affection (MAA) programs are intensive programs with an overall focus on promoting breastfeeding, in addition to ongoing efforts through health systems.

13. Answer a
    - The main objective of Pradhan Mantri School for Rising India PM Shree Scheme is to upgrade almost all the old schools in India. All those schools have to be linked with the new education policy. Through which schools will be made modern. Through which schools will be provided education with modern new technology.
    - Through this scheme, schools having primary school and secondary/senior secondary school, Central State Union Territory government school will be selected under the scheme.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

10. उत्तर D
    - मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिये "'मिशन इंद्रधनुष'" को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 प्रारंभ किया गया था।

11. उत्तर D

    निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) एकमात्र पोलियो वैक्सीन है जो 2000 से संयुक्त राज्य अमेरिका में दी जा रही है। आईपीवी रोगी की उम्र के आधार पर पैर या बांह में गोली द्वारा दिया जाता है।
    रोटावायरस वैक्सीन बच्चों को रोटावायरस से संक्रमित होने से रोकने में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। यह रोटावायरस से पीड़ित प्रत्येक 10 में से 8 शिशुओं में रोटावायरस संक्रमण को रोकता है। बच्चों को यह 2 और 4 महीने की उम्र में और फिर 6 महीने में मिलता है।
    खसरा, मम्प्स और रूबेला (MMR) टीका एक संयोजन टीका है जो इन तीन गंभीर वायरल संक्रमणों से बचाने में मदद करता है।

12. उत्तर B

    माँ का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से चल रहे प्रयासों के अलावा, स्तनपान को बढ़ावा देने पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने के प्रयास के साथ एक गहन कार्यक्रम हैं।

13. उत्तर A

    प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में लगभग पुराने स्कूलों को अपग्रेड करना है। उन सभी स्कूलों को नए शिक्षा नीति के साथ जोड़ना है। जिसके माध्यम से स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा। जिसके माध्यम से स्कूलों को शिक्षा को आधुनिक नई तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जाएगा।
    इस योजना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारी स्कूल वाले स्कूलों की योजना के तहत चयन किया जाएगा।

14. Answer b
- In a historic step aimed at bringing transformational change in the field of nursing education and practice, Parliament has passed the National Nursing and Midwifery Commission (NNMC) Bill, 2023.
- The Act will replace the existing Indian Nursing Council with a modern regulatory structure, marking a significant legislative reform in the field.
- The NNMC Act, 2023 introduces several important provisions to raise the standards of nursing education and services, enhance professional conduct and ensure greater transparency and accountability.

15. Answer b
- Consequent to the announcement of Union Budget 2017-18, Dairy Processing and Infrastructure Development Fund has been set up with a corpus of Rs. 8,004 crore with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
- It aims to provide subsidized loans at the rate of 6.5% primarily to capital stressed milk cooperatives for replacing their decades old cooling and processing plants and adding value added product plants.

16. Answer d
- VKY is broadly a process which aims at holistic development of the tribal people with a result-based approach, which will ensure that all the desired benefits and objects are delivered to the tribal people through various programs/schemes of the Central and State Governments. Services will be provided.
- Under the Viswas Yojana scheme, the government provides financial assistance up to Rs 3 lakh. The thing to note is that there is no need to give any guarantee against this loan. Under this scheme, there are some prescribed rules.
- Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) is a scheme designed to address the developmental deficiencies of identified minority concentrated areas. Before the PMJVK, the ministry had implemented multi-sector development programmes.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

14. उत्तर B
- नर्सिंग शिक्षा और प्रैक्टिस के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम के तहत संसद ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) विधेयक, 2023 पारित किया है।
- यह अधिनियम मौजूदा भारतीय नर्सिंग परिषद को एक आधुनिक नियामक संरचना के साथ बदल देगा, जो क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधायी सुधार को चिन्हित करता हैं।
- एनएनएमसी अधिनियम, 2023, नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं के मानकों को ऊंचा उठाने, पेशेवर आचरण को बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान पेश करता हैं।

15. उत्तर B
- केंद्रीय बजट 2017-18 की घोषणा के परिणामस्वरूप, रुपये के कोष के साथ डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ 8,004 करोड़।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने दशकों पुराने शीतलन और प्रसंस्करण संयंत्रों को बदलने और मूल्य वर्धित उत्पाद संयंत्रों को जोड़ने के लिए पूंजीगत तनावग्रस्त दूध सहकारी समितियों को 6.5% की दर से सब्सिडी वाला ऋण प्रदान करना है।

16. उत्तर D
- वीकेवाई मोटे तौर पर एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य परिणाम-आधारित दृष्टिकोण के साथ जनजातीय लोगों का समग्र विकास करना है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों को सभी इच्छित लाभ वाली वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- विस्वास योजना योजना के तहत सरकार 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. गौर करने वाली बात यह है कि इस लोन के बदले कोई गारंटी देने की भी आवश्यकता नहीं है. इस योजना के तहत, कुछ निर्धारित नियम हैं।
- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) एक योजना है जो चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई है। पीएमजेवीके से पहले , मंत्रालय ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम लागू किया था।

17. Ans c

- 'Flipping' is the process of transferring the entire ownership of a domestic company to an overseas entity, accompanied by a transfer of all IP and all data hitherto owned by the domestic company. It effectively transforms a domestic company into a 100 percent subsidiary of a foreign entity, with the founders and investors retaining the same ownership via the foreign entity, having swapped all shares. Hence, statements 1 and 2 are correct.
- Presence of tax treatments like no withholding taxes, exemptions on dividends and capital gains in foreign jurisdictions (ex: UAE, Netherlands, etc.) Hence, statement 3 is correct.

18. Answer A

- Since the agricultural year 2018-19, the government has ensured a minimum of 50 percent margin over the all-India weighted average cost of production for each crop covered under MSP. Hence statement 1 is correct.
- This price support also aims to reduce India's import dependence and foster diversification towards pulses, oil, and commercial crops. Accordingly, the highest increase in MSP was approved for lentils (masur) at ₹425 per quintal, followed by rapeseed and mustard at ₹200 per quintal in 2023-24. Hence Statement 2 is not correct.

19. Answer B

- As per the World Migration Report 2022, almost 36 per cent of India's remittances are attributable to the high-skilled and largely high-tech Indian migrants in the top high-income destinations. Hence statement 1 is not correct.
- In FY23, the private transfer receipts, mainly representing remittances by Indians, soared to a record USD 112.5 billion level, growing at 26.2 per cent on the back of healthy growth of 11.2 percent in FY22. Hence statement 2 is correct.

17. उत्तर a

'फ़्लिपिंग' एक घरेलू कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जिसमें घरेलू कंपनी के स्वामित्व वाले सभी आईपी और सभी डेटा का हस्तांतरण शामिल है। यह प्रभावी रूप से एक घरेलू कंपनी को एक विदेशी इकाई की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी में बदल देता है, जिसमें संस्थापक और निवेशक विदेशी इकाई के माध्यम से समान स्वामित्व बनाए रखते हैं, सभी शेयरों की अदला-बदली करते हैं। इसलिए, कथन 1 और 2 सही हैं।
विदेशी न्यायक्षेत्रों (जैसे: संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, आदि) में कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं, लाभांश और पूंजीगत लाभ पर छूट जैसे कर उपचारों की उपस्थिति, इसलिए, कथन 3 सही है।

18. उत्तर a

कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से, सरकार ने एमएसपी के तहत कवर की गई प्रत्येक फसल के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सुनिश्चित किया है। अतः कथन 1 सही है।
इस मूल्य समर्थन का उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करना और दालों, तेल और वाणिज्यिक फसलों के प्रति विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है। तदनुसार, 2023-24 में मसूर (मसूर) के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि ₹425 प्रति क्विंटल, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए ₹200 प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

19. उत्तर b

विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत का लगभग 36 प्रतिशत प्रेषण शीर्ष उच्च आय वाले गंतव्यों में उच्च-कुशल और बड़े पैमाने पर उच्च तकनीक वाले भारतीय प्रवासियों के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
वित्त वर्ष 2023 में, निजी हस्तांतरण प्राप्तियां, जो मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिकॉर्ड 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गईं, जो वित्त वर्ष 22 में 11.2 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि के साथ 26.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं। अतः कथन 2 सही है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

20. Answer D

- In the new millennium, India's Female LFPR (FLFPR) declined measurably, accompanied by a steep rise in the enrollment of females in education. FLFPR has been rising for at least six years now: it rose from 23.3 percent in 2017-18 to 37 per cent in 2022-23. While urban FLFPR has also been rising, the rural FLFPR has seen a sharp growth. The rise in rural female LFPR has been accompanied by a rise in the share of self-employment and agriculture among working women. Hence statement 1 is not correct.
- While the composition of the female workforce has been tilting towards agriculture, that of the male workforce is tilting away from agriculture. The rise in the share of agriculture in the rural female workforce from 73.2 per cent in 2017-18 to 76.2 per cent in 2022-23 coincides with a more significant decline in the share of agriculture in the rural male workforce from 55 per cent in 2017-18 to 49.1 percent in 2022-23. This is plausibly due to men taking up rising opportunities in non-agriculture and women at home filling in for the men on the farm. Hence statement 2 is not correct.

21. Answer A

- Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) are becoming increasingly vibrant and dynamic, with the supportive measures implemented by the government. The Union Budget for FY24 has facilitated the timely receipt of payments for MSMEs by allowing a tax deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Hence statement 1 is correct.
- Sections 15 to 24 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, mandate that a buyer is liable to pay interest on delayed payments to MSMEs. Since payment of such interest is considered penal in nature, no deduction for such interest is allowed under section 37 of the Income Tax Act, 1961. Hence statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

20. उत्तर d

नई सहस्राब्दी में, भारत की महिला एलएफपीआर (एफएलएफपीआर) में उल्लेखनीय गिरावट आई, साथ ही शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में भारी वृद्धि हुई। एफएलएफपीआर अब कम से कम छह वर्षों से बढ़ रहा है: यह 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गया। जबकि शहरी एफएलएफपीआर भी बढ़ रहा है, ग्रामीण एफएलएफपीआर में तेज वृद्धि देखी गई है। ग्रामीण महिला एलएफपीआर में वृद्धि के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं के बीच स्व-रोज़गार और कृषि की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
जहां महिला कार्यबल का झुकाव कृषि की ओर हो रहा है, वहीं पुरुष कार्यबल का झुकाव कृषि से दूर हो रहा है। ग्रामीण महिला कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 2017-18 में 73.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 76.2 प्रतिशत हो गई है, जो 2017 में ग्रामीण पुरुष कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक महत्वपूर्ण गिरावट के साथ मेल खाती है। 2022-23 में -18 से 49.1 प्रतिशत। ऐसा संभवतः पुरुषों द्वारा गैर-कृषि क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने और घरेलू महिलाओं द्वारा खेतों में पुरुषों की जगह लेने के कारण हुआ है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

21. उत्तर a

सरकार द्वारा लागू किए गए सहायक उपायों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तेजी से जीवंत और गतिशील हो रहे हैं। वित्त वर्ष 24 के लिए केंद्रीय बजट ने एमएसएमई के लिए भुगतान की समय पर प्राप्ति की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें किए गए भुगतान पर किए गए व्यय के लिए कर कटौती की अनुमति दी गई है, जब भुगतान वास्तव में किया गया हो। अतः कथन 1 सही है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 से 24 में कहा गया है कि खरीदार एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है। चूंकि इस तरह के ब्याज का भुगतान प्रकृति में दंडात्मक माना जाता है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत ऐसे ब्याज के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

22. Answer A

- Considering the importance of the availability of labour force data at more frequent time intervals, the National Statistical Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation launched the Periodic Labour Force Survey (PLFS) in April 2017. Hence option 1 is not correct.
- The Annual Survey of Industries (ASI), conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, is an important source of industrial statistics of the registered organized manufacturing sector of the economy. Hence option 2 is not correct.
- The Labour Bureau has recently been tasked with five major All India Surveys by the Government of India. The five surveys are the All-India Survey of Migrant Workers, All-India Survey on Domestic Workers, All-India Survey on Employment generated in the Transport Sector, All-India Survey of Employment Generated by Professionals and All-India Quarterly Establishment-based Employment Survey (AQEES). Hence option 3 is correct.

23. Answer B

- India's exports have been showing remarkable performance, logging record-high levels since FY22, with merchandise exports rising by more than 50 per cent and services exports by 120 percent over the past decade (FY13 to FY23). The highest-ever merchandise export of USD 451.1 billion was achieved in FY23. Hence statement 1 is not correct.
- In the export of services, India has carved a niche for itself as a knowledge-based economy, as is evident from the fact that software services exports comprise almost half of the service exports consistently. Further, a gradual increase in the share of business services in total services exports has been noticed since FY20. Hence statement 2 is correct.
- The government released the Foreign Trade Policy (FTP) 2023 which aimed to increase the country's exports to USD 2 trillion by 2030.

22. उत्तर ए

अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) लॉन्च किया। इसलिए विकल्प 1 सही नहीं है .

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई), अर्थव्यवस्था के पंजीकृत संगठित विनिर्माण क्षेत्र के औद्योगिक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः विकल्प 2 सही नहीं है।

श्रम ब्यूरो को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पांच प्रमुख अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का काम सौंपा गया है। पांच सर्वेक्षण हैं प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, घरेलू श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, परिवहन क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण और अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना-आधारित सर्वेक्षण। रोजगार सर्वेक्षण (AQEES)। अतः विकल्प 3 सही है।

23. उत्तर b

भारत का निर्यात उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखा रहा है, वित्त वर्ष 2012 के बाद से रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर प्रवेश कर रहा है, पिछले दशक (वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 23) में माल निर्यात में 50 प्रतिशत से अधिक और सेवाओं के निर्यात में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। FY23 में 451.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक व्यापारिक निर्यात हासिल किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।

सेवाओं के निर्यात में, भारत ने ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में लगातार सेवा निर्यात का लगभग आधा हिस्सा शामिल है। इसके अलावा, FY20 के बाद से कुल सेवा निर्यात में व्यावसायिक सेवाओं की हिस्सेदारी में क्रमिक वृद्धि देखी गई है। अतः कथन 2 सही है।

सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 जारी की जिसका लक्ष्य 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

24. Answer D

- The Indian agriculture sector has been growing at an average annual growth rate of 4.6 percent during the last six years. Hence statement 1 is not correct.
- In recent years, India has also rapidly emerged as the net exporter of agricultural products. In 2020-21, exports of agriculture and allied products from India grew by 18 percent over the previous year. During 2021-22 itself, agricultural exports reached an all-time high of US$ 50.2 billion. Hence statement 2 is not correct.

25. Answer B

- According to the Economic Survey 2022-23, India's economic growth in FY23 has been principally led by private consumption and capital formation. The agencies worldwide have projected India as the fastest-growing major economy at 6.5-7.0 percent in FY23. Hence option 3 is correct.
- The Capital Expenditure (Capex) of the central government, which increased by 63.4 percent in the first eight months of FY23, was another principal growth driver of the Indian economy in the current year.
- India's current account balance (CAB) recorded a deficit of US$ 36.4 billion (4.4 percent of GDP) in Q2FY23 in contrast to a deficit of US$ 9.7 billion (1.3 percent of GDP) during the corresponding period of the previous year. The widening of the current account deficit (CAD) in the second quarter of FY23 was mainly on account of a higher merchandise trade deficit of US$ 83.5 billion and an increase in net investment income outgo. Hence, India did not have a Current Account Surplus in FY 23. Hence option 4 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

24. उत्तर d

भारतीय कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
हाल के वर्षों में भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी उभरा है। 2020-21 में भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ गया। 2021-22 के दौरान ही कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

25. उत्तर b

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से निजी उपभोग और पूंजी निर्माण के कारण हुई है। दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को FY23 में 6.5-7.0 प्रतिशत की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया है। अतः विकल्प 3 सही है।
केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), जो वित्त वर्ष 2013 के पहले आठ महीनों में 63.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और प्रमुख विकास चालक था।

भारत के चालू खाते के शेष (CAB) में Q2FY23 में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 4.4 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 1.3 प्रतिशत) का घाटा था। वित्त वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) का बढ़ना मुख्य रूप से 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च व्यापारिक व्यापार घाटे और शुद्ध निवेश आय व्यय में वृद्धि के कारण था। इसलिए, वित्त वर्ष 23 में भारत के पास चालू खाता अधिशेष नहीं था। इसलिए विकल्प 4 सही नहीं है।

26. Answer A

- The Employees Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) is an insurance scheme that was launched by the Government in 1976. Hence statement 2 is not correct.
- There is no need for the employees to contribute to EDLI. Their contribution is required only for EPF (rather Employer has to contribute on behalf of the employee). Hence statement 1 is not correct.
- Any organization that has more than 20 employees needs to register for EPF. Therefore, any employee who has an EPF account automatically becomes eligible for the EDLI scheme. Hence statement 3 is correct.

27. Answer d

- The top 5 sectors receiving the highest FDI Equity Inflow during FY 2022-23 are Services Sector (Finance, Banking, Insurance, Non-Fin/ Business, Outsourcing, R&D, Courier, Tech. Testing and Analysis, Other) (16%), Computer Software & Hardware (15%), Trading (6%), Telecommunications (6%) and Automobile Industry (5%). Hence option (c) is the correct answer.

28. Answer B

- The international investment position (IIP) is the balance sheet of a country's external financial assets and liabilities. It is an indicator of the degree of financial openness of a country. Hence statements 1 and 2 are correct.
- India's IIP position, on the whole, has remained stable during the past decade. As of September 2023, total liabilities, which largely comprise investments by non-residents, increased by 6.5 percent (YoY), while total assets, which largely comprise reserve assets, increased by 10.2 per cent (YoY). Hence statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

26. उत्तर a

कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) एक बीमा योजना है जिसे सरकार द्वारा 1976 में शुरू किया गया था। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
कर्मचारियों को EDLI में योगदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका योगदान केवल EPF के लिए आवश्यक है (बल्कि नियोक्ता को कर्मचारी की ओर से योगदान करना होता है)। अतः कथन 1 सही नहीं है।
कोई भी संगठन जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी हों, उसे ईपीएफ के लिए पंजीकरण कराना होगा। इसलिए, कोई भी कर्मचारी जिसके पास ईपीएफ खाता है वह स्वचालित रूप से ईडीएलआई योजना के लिए पात्र हो जाता है। अतः कथन 3 सही है।

27. उत्तर d

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आर एंड डी, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य) (16%) हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (15%), ट्रेडिंग (6%), दूरसंचार (6%) और ऑटोमोबाइल उद्योग (5%)। अतः विकल्प (सी) सही उत्तर है।

28. उत्तर बी

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) किसी देश की बाहरी वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की बैलेंस शीट है। यह किसी देश के वित्तीय खुलेपन की डिग्री का संकेतक है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं।
कुल मिलाकर, भारत की आईआईपी स्थिति पिछले दशक के दौरान स्थिर रही है। सितंबर 2023 तक, कुल देनदारियां, जिसमें बड़े पैमाने पर गैर-निवासियों द्वारा निवेश शामिल है, 6.5 प्रतिशत (YoY) की वृद्धि हुई, जबकि कुल संपत्ति, जिसमें बड़े पैमाने पर आरक्षित संपत्तियां शामिल हैं, 10.2 प्रतिशत (YoY) की वृद्धि हुई। अतः कथन 3 सही नहीं है।

29. Answer B

- Revenue Expenditure is part of government spending that does not result in the production of assets. The significant components of the Centre's revenue expenditure include Interest payments, major subsidies, salaries of Government employees, pensions, defense revenue expenditure and transfers to States.
- Construction of National Highways is covered under Capital Expenditure as it leads to asset creation.

• Hence, option (b) is the correct answer.

30. Answer C

- Pent-up demand refers to a situation where demand for a service or product is unusually strong. Pent-up demand describes a rapid increase in demand for a service or product, usually following a period of subdued spending. Hence statement II is not correct.
- Consumers tend to hold off making purchases during a recession, building up a backlog of demand that is unleashed when signs of a recovery emerge.
- Pent-up demand is especially evident with big-ticket, durable goods. When economic times get tough, consumers tend to refrain from making expensive, big-ticket purchases such as vehicles, appliances, and other durable goods, instead opting to make what they have lasted longer—even if it requires extra maintenance and repairs. Once conditions improve, there is a surge in spending. Hence statement I is correct.

31. Answer D

- As per the RBI data, in FY 22, the total amount recovered by Scheduled Commercial Banks (SCBs) under IBC has been the highest compared to other channels such as Lok Adalat, SARFAESI Act and Debts Recovery Tribunals (DRTs) in this period. Hence option (d) is the correct answer.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

29. उत्तर b

राजस्व व्यय सरकारी खर्च का हिस्सा है जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का उत्पादन नहीं होता है। केंद्र के राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण घटकों में ब्याज भुगतान, प्रमुख सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय और राज्यों को स्थानांतरण शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है क्योंकि इससे संपत्ति निर्माण होता है।
इसलिए, विकल्प (बी) सही उत्तर है।

30. उत्तर c

दबी हुई मांग उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां किसी सेवा या उत्पाद की मांग असामान्य रूप से मजबूत होती है। दबी हुई मांग किसी सेवा या उत्पाद की मांग में तेजी से वृद्धि का वर्णन करती है, जो आमतौर पर कम खर्च की अवधि के बाद होती है। अतः कथन II सही नहीं है।
उपभोक्ता मंदी के दौरान खरीदारी करना बंद कर देते हैं, जिससे मांग का बैकलॉग तैयार हो जाता है, जो सुधार के संकेत मिलने पर सामने आता है।
दबी हुई मांग विशेष रूप से बड़े-टिकट वाले, टिकाऊ सामानों के साथ स्पष्ट है। जब आर्थिक समय कठिन हो जाता है, तो उपभोक्ता वाहन, उपकरण और अन्य टिकाऊ सामान जैसी महंगी, बड़ी खरीदारी करने से बचते हैं, इसके बजाय वे वही बनाते हैं जो लंबे समय तक चलता है - भले ही इसके लिए अतिरिक्त रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता हो। एक बार हालात बेहतर होने पर खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है। अतः कथन I सही है।

31. उत्तर d

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 22 में, आईबीसी के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा वसूल की गई कुल राशि इस अवधि में लोक अदालत, सरफेसी अधिनियम और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) जैसे अन्य चैनलों की तुलना में सबसे अधिक रही है। अतः विकल्प (डी) सही उत्तर है।

32. Answer A

- The number of tax slabs has been reduced from six to five. The surcharge on the income when it exceeds Rs 5 crore will be reduced from 37% to 25%. Currently, those with income up to Rs 5 lakh can avail of a rebate and not pay any taxes; this limit has been raised to Rs 7 lakh. Further, the standard deduction will be available under the new tax regime. Hence statement 1 is correct.
- The highest income tax slab under both regimes is above 15 lakhs with a 30% tax rate. Hence statement 2 is not correct.

33. Answer B

- India maintained its dominance in the world services trade in FY22. It is the 7th largest service exporter in the world. Hence statement 1 is not correct.
- Software and business services together constitute more than 60 percent of India's total services exports and exhibited strong growth during Q2FY23. Hence statement 2 is correct.

34. Answer C

- Monetary Authority of Singapore (MAS) and the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) have signed a FinTech Co-operation Agreement (CA) to facilitate regulatory collaboration and partnership in FinTech to promote a Joint Regulatory Sandbox Collaboration that will leverage existing regulatory sandboxes in their respective jurisdictions to support experimentation of technology innovations.
- The Agreement will enable FinTech firms from one jurisdiction to gain market access in the other jurisdiction through a regulatory referral system. Hence, option (c) is the correct answer.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

32. उत्तर a

टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है. 5 करोड़ रुपये से अधिक आय होने पर सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया जाएगा। वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोग छूट का लाभ उठा सकते हैं और कोई कर नहीं देना होगा; यह सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती उपलब्ध होगी। अतः कथन 1 सही है।
दोनों व्यवस्थाओं के तहत उच्चतम आयकर स्लैब 30% कर दर के साथ 15 लाख से ऊपर है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

33. उत्तर b

भारत ने FY22 में विश्व सेवा व्यापार में अपना दबदबा बरकरार रखा। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाएँ मिलकर भारत के कुल सेवा निर्यात का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाती हैं और Q2FY23 के दौरान मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की है। अतः कथन 2 सही है।

34. उत्तर c

सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने एक संयुक्त नियामक सैंडबॉक्स सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए एक फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो मौजूदा नियामक सैंडबॉक्स का लाभ उठाएगा। प्रौद्योगिकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करने के लिए उनके संबंधित क्षेत्राधिकार।
यह समझौता फिनटेक फर्मों को एक क्षेत्राधिकार से नियामक रेफरल प्रणाली के माध्यम से दूसरे क्षेत्राधिकार में बाजार पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अतः, विकल्प (सी) सही उत्तर है।

35. Answer C
- According to the Economic Survey 2022-23, India is the fifth largest in market exchange rates.
- As of January 2024, India is not the largest holder of foreign exchange reserves. According to the Reserve Bank of India (RBI)'s website, India's foreign exchange reserves stand at approximately USD 568 billion. Japan currently holds the top spot with reserves exceeding USD 1.3 trillion. Hence, option (c) is the correct answer.

36. Answer D
- With capital expenditure taken together with the provision made for the creation of capital assets through Grants-in-Aid to States is called 'Effective Capital Expenditure' of the Central Government
- It is estimated at Rs. 10.68 lakh crore in 2022-23, which will be about 4.1% of GDP, according to the Finance Minister who announced the data during the budget 2023-24.

Hence, option (d) is the correct answer.

37. Answer C
- This fund will enable inclusive, farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit, and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for the growth of the agri-tech industry and startups.Hence, option (c) is the correct answer.

38. Answer D
- In its recent report on municipal finances, RBI pointed out that India's property tax collection was much lower than the OECD countries. While the average collection from property taxes as a proportion of GDP was 1.1% in the OECD, it was only 0.2% in India. Hence, statement 1 is not correct.
- Lower property tax collection in India can be attributed to several factors including property undervaluation, incomplete registers, policy inadequacy, and ineffective administration.
- According to ESI 2022-23, there is a wide disparity in taxes across the States, thus creating scope for a large-scale reform of property taxation practices in India. Hence, statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

35. उत्तर c

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत विनिमय दरों में पांचवें स्थान पर है।
जनवरी 2024 तक, भारत विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा धारक नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वेबसाइट के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 568 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जापान वर्तमान में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक भंडार के साथ शीर्ष स्थान पर है। अतः, विकल्प (सी) सही उत्तर है।

36. उत्तर d

राज्यों को अनुदान सहायता के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान के साथ पूंजीगत व्यय को केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' कहा जाता है।
इसकी अनुमानित कीमत रु. बजट 2023-24 के दौरान आंकड़ों की घोषणा करने वाले वित्त मंत्री के अनुसार, 2022-23 में 10.68 लाख करोड़, जो जीडीपी का लगभग 4.1% होगा।
इसलिए, विकल्प (डी) सही उत्तर है।

37. उत्तर c

यह फंड फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि आदानों, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार की जानकारी और कृषि-तकनीक उद्योग के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान सक्षम करेगा। और स्टार्टअप। इसलिए, विकल्प (सी) सही उत्तर है।

38. उत्तर d

नगरपालिका वित्त पर अपनी हालिया रिपोर्ट में, आरबीआई ने बताया कि भारत का संपत्ति कर संग्रह ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम था। जबकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में संपत्ति कर से औसत संग्रह ओईसीडी में 1.1% था, भारत में यह केवल 0.2% था। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
भारत में कम संपत्ति कर संग्रह को संपत्ति के कम मूल्यांकन, अपूर्ण रजिस्टर, नीति अपर्याप्तता और अप्रभावी प्रशासन सहित कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
ईएसआई 2022-23 के अनुसार, राज्यों में करों में व्यापक असमानता है, जिससे भारत में संपत्ति कराधान प्रथाओं में बड़े पैमाने पर सुधार की गुंजाइश पैदा हो रही है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

39. Answer A
- India meets 60 percent of its edible oils demand through imports, making it vulnerable to international movements in prices. Hence, statement 1 is correct.
- Sunflower oil alone makes up 15 percent of India's total edible oil imports and is procured mainly from Ukraine and Russia. India buys palm oil mainly from Indonesia, Malaysia, and Thailand, while it imports soybean oil needs from Argentina and the rest from Brazil. Hence, statement 2 is not correct and statement 3 is not correct.

40. Answer D
- China is the third top remittance recipient of the world after India and Mexico in 2023. Hence statement 1 is not correct.
- As of end-November 2022, India was the sixth largest foreign exchange reserves holder in the world according to data compiled by the IMF. Hence statement 2 is not correct.

41. Answer C
- Regarding the composition of works, the share of "works done on individual's land" (included in the permissible work list in 2009 and expanded since then) has increased from 16 percent of the total completed works in FY15 to 73 percent in FY22.

42. Answer C
- According to the Interim Budget estimates for 2024-25, Direct taxes (income tax, corporate tax, etc.) accounted for 6.7 percent of GDP, and indirect taxes (Goods and Services Tax, Central Excise, etc.) accounted for 4.9 per cent of the total central tax collection in India. Hence, statement 1 is correct.
- The Income Tax Act, of 1961 levies a corporate tax on domestic as well as foreign companies. The Government of India, through this Act, mandates domestic companies to pay corporate taxes based on their universal income. Hence statement 3 is correct.
- Goods and Services Tax constitutes 28 percent of total tax collection as compared to Corporation Income Tax which constitutes 26 percent of total tax collection. Hence, statement 2 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

39. उत्तर a

भारत अपने खाद्य तेलों की 60 प्रतिशत मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिससे यह कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अतः, कथन 1 सही है।

अकेले सूरजमुखी तेल भारत के कुल खाद्य तेल आयात का 15 प्रतिशत बनाता है और मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से खरीदा जाता है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम तेल खरीदता है, जबकि सोयाबीन तेल की जरूरत अर्जेंटीना से और बाकी ब्राजील से आयात करता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है और कथन 3 सही नहीं है।

40. उत्तर d

2022 में भारत और मैक्सिको के बाद चीन दुनिया का तीसरा शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।
आईएमएफ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2022 के अंत तक, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

41. उत्तर c

कार्यों की संरचना के संबंध में, "व्यक्ति की भूमि पर किए गए कार्यों" (2009 में अनुमत कार्य सूची में शामिल और तब से विस्तारित) का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 में कुल पूर्ण कार्यों के 16 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 73 प्रतिशत हो गया है।

42. उत्तर c

2024-25 के अंतरिम बजट अनुमान के अनुसार, प्रत्यक्ष कर (आयकर, कॉर्पोरेट कर, आदि) सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत था, और अप्रत्यक्ष कर (वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आदि) 4.9 प्रतिशत था। भारत में कुल केंद्रीय कर संग्रह का. अतः, कथन 1 सही है।
1961 का आयकर अधिनियम घरेलू और विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाता है। भारत सरकार, इस अधिनियम के माध्यम से, घरेलू कंपनियों को उनकी सार्वभौमिक आय के आधार पर कॉर्पोरेट करों का भुगतान करने का आदेश देती है। अतः कथन 3 सही है।
वस्तु एवं सेवा कर कुल कर संग्रह का 28 प्रतिशत है जबकि निगम आयकर कुल कर संग्रह का 26 प्रतिशत है। अतः, कथन 2 सही है।

43. Answer A

- Fiscal Deficit refers to the difference between a government's total revenue and expenses in a given fiscal year. Hence, statement 1 is correct.
- For FY24 the fiscal gap has been cut to 5.8 per cent as against the estimated 5.9 per cent. The number for 2024-25 has been fixed at 5.1%, below the revised budget for 2023-24, stating that the aim is to achieve a fiscal deficit target of below 4.5 percent by 2025-26. Hence, statement 2 is not correct.

44. Answer : a

Digital Markets Act (DMA)

The Digital Markets Act (DMA) was established by the European Union.

DMA establishes a set of narrowly defined objective criteria for qualifying a large online platform as a so-called gatekeeper.

This allows the DMA to remain well targeted to the problem that it aims to tackle as regards large, systemic online platforms.

Has a strong economic position, significant impact on the internal market and is active in multiple EU countries.

Has (or is about to have) an entrenched and durable position in the market, meaning that it is stable over time if the company met the two criteria above in each of the last three financial years.

Business users who depend on gatekeepers to offer their services in the single market will have a fairer business environment.

Consumers will have more and better services to choose from, more opportunities to switch their provider if they wish so, direct access to services, and fairer prices.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

43. उत्तर a

राजकोषीय घाटा किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। अतः, कथन 1 सही है।

FY24 के लिए राजकोषीय अंतर को अनुमानित 5.9 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया है। 2024-25 के लिए संख्या 2023-24 के संशोधित बजट से नीचे 5.1% तय की गई है, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्य 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

44. उत्तर: ए

डिजिटल बाज़ार अधिनियम (डीएमए)

डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित किया गया था।

डीएमए एक बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को तथाकथित द्वारपाल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए संकीर्ण रूप से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों का एक सेट स्थापित करता है।

यह डीएमए को उस समस्या पर अच्छी तरह से लक्षित रहने की अनुमति देता है जिसका लक्ष्य बड़े, प्रणालीगत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से निपटना है।

एक मजबूत आर्थिक स्थिति है, आंतरिक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और कई यूरोपीय संघ के देशों में सक्रिय है।

बाज़ार में एक मजबूत और टिकाऊ स्थिति है (या होने वाली है), जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ स्थिर है यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में उपरोक्त दो मानदंडों को पूरा करती है।

व्यावसायिक उपयोगकर्ता जो एकल बाज़ार में अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए द्वारपालों पर निर्भर हैं, उनके पास बेहतर व्यावसायिक वातावरण होगा।

उपभोक्ताओं के पास चुनने के लिए अधिक और बेहतर सेवाएँ होंगी, यदि वे चाहें तो अपने प्रदाता को बदलने के अधिक अवसर होंगे, सेवाओं तक सीधी पहुँच होगी और उचित कीमतें होंगी।

45. Answer C

- With a thrust on investment in infrastructure, the Union Ministry of Railways has been allocated ₹2.55 lakh crore for the financial year 2024-25, up by 5.8% from last year's allocation of ₹2.41 lakh crore.
- Union Finance Minister, in her Budget speech, said that the Centre will implement three major economic railway corridor programmes—

o Energy, mineral and cement corridor, also being referred to as Energy Economic Corridor;
o port connectivity corridor a.k.a Rail Sagar; and
o high traffic density corridors a.k.a Amrit Chaturbhu

46. Answer C

- A notable initiative includes viability gap funding for the development of 1 gigawatt (GW) of offshore wind energy, which is expected to play a crucial role in diversifying India's renewable energy portfolio and reducing reliance on fossil fuels.
- Another key component of the strategy is the ambitious goal to set up coal gasification and liquefaction projects capable of processing 100 metric tonnes by 2030.
- To further reduce carbon emissions, the government plans to mandate the blending of biogas with compressed natural gas (CNG) for transportation and piped natural gas for domestic use. This policy is expected to not only improve air quality but also boost the biogas industry, contributing to the circular economy.
- Financial assistance will be provided to support the procurement of biomass aggregation, which is essential for the production of bioenergy

45. उत्तर c

बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर देने के साथ, केंद्रीय रेल मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.55 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछले साल के ₹2.41 लाख करोड़ के आवंटन से 5.8% अधिक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू करेगा-
o ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, जिसे ऊर्जा आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है;
o पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर उर्फ रेल सागर; और
o उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे अर्थात अमृत चतुर्भुज

46. उत्तर c

एक उल्लेखनीय पहल में 1 गीगावाट (जीडब्ल्यू) अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण शामिल है, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
रणनीति का एक अन्य प्रमुख घटक 2030 तक 100 मीट्रिक टन प्रसंस्करण में सक्षम कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण परियोजनाएं स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
कार्बन उत्सर्जन को और कम करने के लिए, सरकार परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस के साथ बायोगैस के मिश्रण को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इस नीति से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए बायोगैस उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

बायोमास एकत्रीकरण की खरीद का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो बायोएनर्जी के उत्पादन के लिए आवश्यक है

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

47. Answer A

- The finance minister in her Budget Speech made an announcement to set up the Bharat Shared Repository of Inscriptions (BharatSHRI), a digital epigraphy museum, with the digitization of one lakh ancient inscriptions in the first stage. Hence statement 1 is correct.
- The BharatSHRI will be set up by the Archaeological Survey of India at Hyderabad. Hence statement 2 is not correct.

48. Answer D

- Pradhan Mantri Awas Yojana (rural and urban components taken together) has the highest allocation in 2023-24 at Rs 79,590 crore.
- The government attracted criticism due to the significant reduction in the MGNREGA outlays.Also, The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has seen no improvement in terms of allocation as the allocation remains the same as last year despite a major infrastructure push by the government.Hence, statements 2 and 3 are not correct.

49. Answer C

- Automotive Mission Plan 2026 has been finalized jointly by the Government of India and the Indian Automotive Industry. Hence, statement 1 is correct.
- The AMP 2026 is aimed at bringing the Indian Automotive Industry among the top three of the world in engineering, manufacturing, and exports of vehicles & components; growing in value to over 12% of India's GDP and generating an additional 65 million jobs. Hence, statement 2 is correct.
- It envisages implementing the End of Life Policy for automotive vehicles and components.Hence, statement 3 is correct.

47. उत्तर ए

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहले चरण में एक लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, भारत साझा शिलालेख भंडार (भारतश्री) स्थापित करने की घोषणा की। अतः कथन 1 सही है।
भारतश्री की स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हैदराबाद में की जाएगी। अतः कथन 2 सही नहीं है।

48. उत्तर d

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर) का आवंटन 2023-24 में सबसे अधिक 79,590 करोड़ रुपये है।
मनरेगा परिव्यय में उल्लेखनीय कमी के कारण सरकार की आलोचना हुई। इसके अलावा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आवंटन के मामले में कोई सुधार नहीं देखा गया है क्योंकि सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचे पर जोर देने के बावजूद आवंटन पिछले वर्ष के समान ही है। इसलिए, कथन 2 और 3 सही नहीं हैं।

49. उत्तर c

ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 को भारत सरकार और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया गया है। अतः, कथन 1 सही है।

एएमपी 2026 का उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को इंजीनियरिंग, विनिर्माण और वाहनों और घटकों के निर्यात में दुनिया के शीर्ष तीन में लाना है; भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 12% से अधिक मूल्य में वृद्धि और अतिरिक्त 65 मिलियन नौकरियां पैदा करना। अतः, कथन 2 सही है।
इसमें ऑटोमोटिव वाहनों और घटकों के लिए जीवन समाप्ति नीति को लागू करने की परिकल्पना की गई है। इसलिए, कथन 3 सही है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

50. Answer C

- Indian Market is the world's fourth-largest stock market in terms of market capitalization. India's market capitalization to GDP ratio has improved from 79 % in 2014 to 104 % in 2022. The Indian benchmark equity indices (Sensex & Nifty 50) delivered a CAGR of about 13.5 % during 2014 -2023.
- India has the second-largest weightage in the MSCI Emerging Markets index. Hence statement 1 is not correct.
- RBI's Retail Direct scheme allowed individual investors to subscribe to government securities such as sovereign bonds and sovereign gold bonds. Hence statement 2 is not correct.
- SEBI introduced a framework whereby listed large corporates will mandatorily meet 25 % of their financing needs through the issuance of debt securities. Hence statement 3 is correct.

51. Answer A

- To provide financial assistance to financially unviable but socially/ economically desirable PPP projects, the Department of Economic Affairs (DEA) launched the Viability Gap Funding (VGF) scheme in 2006. Hence, statement 1 is correct.
- Economic sectors: transportation, energy, irrigation, etc. Hence, statement 2 is not correct.
- Social sectors may get up to 80 percent of the Capex and 50 per cent of the Operating Expenditure (Opex) for five years after the Commercial Operation Date (CoD) as a VGF grant. Hence, statement 3 is not correct.

52. Answer D

- With shrinking GNPAs, the Provisioning Coverage Ratio (PCR) has been increasing steadily since March 2021 and reached 75.3 percent in September 2023. Hence statement 1 is not correct.
- PCR in the case of the Private sector Banks has consistently remained higher than Public sector banks in the past till September 22 but has overtaken Private Banks by September 2023. Hence, statement 2 is not correct.

50. उत्तर c

बाजार पूंजीकरण के मामले में भारतीय बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 2014 में 79% से बढ़कर 2022 में 104% हो गया है। भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक (सेंसेक्स और निफ्टी 50) ने 2014 -2023 के दौरान लगभग 13.5% का सीएजीआर दिया।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेटेज है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट योजना ने व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों जैसे सॉवरेन बांड और सॉवरेन गोल्ड बांड की सदस्यता लेने की अनुमति दी। अतः कथन 2 सही नहीं है।

सेबी ने एक रूपरेखा पेश की जिसके तहत सूचीबद्ध बड़े कॉरपोरेट अनिवार्य रूप से ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके अपनी वित्तपोषण जरूरतों का 25% पूरा करेंगे। अतः कथन 3 सही है।

51. उत्तर ए

वित्तीय रूप से अव्यवहार्य लेकिन सामाजिक/आर्थिक रूप से वांछनीय पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने 2006 में व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू की। इसलिए, कथन 1 सही है।

आर्थिक क्षेत्र: परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, आदि। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

सामाजिक क्षेत्रों को वीजीएफ अनुदान के रूप में वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के बाद पांच वर्षों के लिए कैपेक्स का 80 प्रतिशत और परिचालन व्यय (ओपेक्स) का 50 प्रतिशत तक मिल सकता है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

52. उत्तर डी

सिकुड़ते जीएनपीए के साथ, प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2021 से लगातार बढ़ रहा है और सितंबर 2023 में 75.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में पीसीआर 22 सितंबर तक लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अधिक रही है, लेकिन सितंबर 2023 तक निजी बैंकों से आगे निकल गई है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

53. Answer C

- A higher credit-to-GDP ratio indicates aggressive and active participation of the banking sector in the real economy, while a lower number shows the need for more formal credit. Hence statement 2 is correct.
- Basel III introduced a countercyclical capital buffer (CCB) aimed at strengthening banks' defenses against the build-up of systemic vulnerabilities. The framework assigns the credit-to-GDP gap a prominent role as a guide for policymakers. The guide is intended to help frame the analysis of whether to activate or increase the required buffer and the communication of the related decisions. Hence statement 1 is correct.

54. Answer B

- Under this scheme, short-term agriculture loan upto Rs. 3.00 lakh is available to farmers engaged in Agriculture and other allied activities including Animal Husbandry, Dairying, Poultry, fisheries etc. at the rate of 7% p.a. Hence statements 1 and 2 are correct.
- MISS covers activities like Animal Husbandry, Dairy, and Fisheries. Hence statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

53. उत्तर सी

उच्च क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात वास्तविक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र की आक्रामक और सक्रिय भागीदारी को इंगित करता है, जबकि कम संख्या अधिक औपचारिक ऋण की आवश्यकता को दर्शाती है। अतः कथन 2 सही है।
बेसल III ने प्रणालीगत कमजोरियों के निर्माण के खिलाफ बैंकों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीबी) की शुरुआत की। यह रूपरेखा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर को एक प्रमुख भूमिका प्रदान करती है। गाइड का उद्देश्य आवश्यक बफर को सक्रिय करने या बढ़ाने और संबंधित निर्णयों के संचार के विश्लेषण में मदद करना है। अतः कथन 1 सही है।

54. उत्तर बी

इस योजना के तहत रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है। कृषि और पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से 3.00 लाख रुपये उपलब्ध हैं। अतः कथन 1 और 2 सही हैं।
MISS पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को कवर करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

55. Answer D

- The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) was announced as part of the Atma Nirbhar Bharat Package in May 2020 to support eligible MSMEs and other business enterprises to meet their operational liabilities and resume business in view of the distress caused by the COVID-19 crisis. This scheme covers all sectors of the economy. Under this, a 100% guarantee is provided to Member Lending Institutions (MLIs) in respect of the credit facility extended by them to eligible borrowers. Hence, statement 3 is correct.
- The Scheme provides 100% guarantee coverage by the National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) to MLIs on GECL of up to Rs.5 lakh crore to eligible MSMEs. MSMEs for the purpose of this Scheme will include MSMEs/ Business Enterprises which are constituted as Proprietorships, Partnerships, Registered Companies, Trusts and Limited Liability Partnerships (LLPs), interested borrowers under Pradhan Mantri Mudra Yojana, and also loans to individuals for business purposes. Hence, statement 1 is correct.
- All Scheduled Commercial Banks (SCBs) are eligible as MLIs. NBFCs which have been in operation for at least 2 years as on 29.2.2020, and All India Financial Institutions will also be eligible as MLIs under the Scheme. Hence, statement 2 is correct.

56. Answer C

- According to Economic Survey 2022-23, India is the third-largest economy in the world in Purchasing power parity (PPP) terms. China and the USA are the leading countries in terms of PPP.
- Purchasing power parities (PPPs) are the rates of currency conversion that try to equalize the purchasing power of different currencies, by eliminating the differences in price levels between countries. Hence option (a) is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

55. उत्तर डी

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, ताकि पात्र एमएसएमई और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और सीओवीआईडी -19 संकट के कारण व्यापार फिर से शुरू करने में सहायता मिल सके। . यह योजना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। इसके तहत सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में 100% गारंटी प्रदान की जाती है। अतः, कथन 3 सही है।

यह योजना पात्र एमएसएमई को 5 लाख करोड़ रुपये तक जीईसीएल पर एमएलआई को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के प्रयोजन के लिए एमएसएमई में एमएसएमई/व्यावसायिक उद्यम शामिल होंगे जो स्वामित्व, साझेदारी, पंजीकृत कंपनियों, ट्रस्ट और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के रूप में गठित हैं, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत इच्छुक उधारकर्ता और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण भी देते हैं। अतः, कथन 1 सही है।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) एमएलआई के रूप में पात्र हैं। एनबीएफसी जो 29.2.2020 तक कम से कम 2 वर्षों से परिचालन में हैं, और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भी योजना के तहत एमएलआई के रूप में पात्र होंगे। अतः, कथन 2 सही है।

56. उत्तर सी

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीपीपी के मामले में चीन और अमेरिका अग्रणी देश हैं।

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) मुद्रा रूपांतरण की दरें हैं जो देशों के बीच मूल्य स्तरों में अंतर को समाप्त करके, विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति को बराबर करने का प्रयास करती हैं। अतः विकल्प (ए) सही है।

57. Answer C

- It has been observed that many Indian companies have been getting headquartered overseas, especially in destinations with favorable legal environments and taxation policies. The technical jargon for this may be identified as 'Flipping.
- 'Flipping' is the process of transferring the entire ownership of a domestic company to an overseas entity, accompanied by a transfer of all IP and all data hitherto owned by the domestic company. It effectively transforms a domestic company into a 100 per cent subsidiary of a foreign entity, with the founders and investors retaining the same ownership via the foreign entity, having swapped all shares.

58. Answer C

- Pent-up demand describes a rapid increase in demand for a service or product, usually following a period of subdued spending. Consumers tend to hold off making purchases during a recession, building up a backlog of demand that is unleashed when signs of a recovery emerge. Hence option (c) is the correct answer.

59. Answer D

The Fund of Funds for Startups (FFS) Scheme was approved and established in 2016 with a corpus of Rs 10,000 crore. So, statement 1 is not correct.

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has been given the mandate of operating this Fund through the selection of suitable daughter funds and overseeing the disbursal of committed capital. So, statement 2 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

57. उत्तर सी

यह देखा गया है कि कई भारतीय कंपनियों का मुख्यालय विदेशों में हो रहा है, खासकर अनुकूल कानूनी माहौल और कराधान नीतियों वाले गंतव्यों में। इसके लिए तकनीकी शब्दजाल को 'फ़्लिपिंग' के रूप में पहचाना जा सकता है।

'फ़्लिपिंग' एक घरेलू कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जिसमें घरेलू कंपनी के स्वामित्व वाले सभी आईपी और सभी डेटा का हस्तांतरण शामिल है। यह प्रभावी रूप से एक घरेलू कंपनी को एक विदेशी इकाई की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी में बदल देता है, जिसमें संस्थापक और निवेशक सभी शेयरों की अदला-बदली करके विदेशी इकाई के माध्यम से समान स्वामित्व बनाए रखते हैं।

58. उत्तर सी

दबी हुई मांग किसी सेवा या उत्पाद की मांग में तेजी से वृद्धि का वर्णन करती है, जो आमतौर पर कम खर्च की अवधि के बाद होती है। उपभोक्ता मंदी के दौरान खरीदारी करना बंद कर देते हैं, जिससे मांग का बैकलॉग तैयार हो जाता है, जो सुधार के संकेत मिलने पर सामने आता है। अतः विकल्प (सी) सही उत्तर है।

59. उत्तर d

स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) योजना को 2016 में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुमोदित और स्थापित किया गया था। अतः, कथन 1 सही नहीं है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को उपयुक्त सहायक निधियों के चयन और प्रतिबद्ध पूंजी के वितरण की देखरेख के माध्यम से इस फंड के संचालन का अधिकार दिया गया है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

60. Answer B

- The government's thrust on CAPEX, particularly in the infrastructure-intensive sectors like roads and highways, railways, and housing and urban affairs, has longer-term implications for growth as it enhances the productive capacity of an economy in the long run. Hence, statement 1 is correct.
- The government's emphasis on capital expenditure provides a boost to private investment due to a decrease in interest rate (crowding in private investment). Crowding out effect, on the other hand, refers to the situation when increased interest rates lead to a reduction in private investment spending such that it dampens the initial increase of total investment spending. Hence, statement 2 is not correct.
- Capital expenditure provides a boost to Aggregate Demand (AD) by giving a boost to Private consumption (C), Investment (I), and Government expenditure (G) components. (AD = C+I+G). Hence, statement 3 is correct.

61. Answer B

- The unemployment rate has declined to 3.2 % in 2022- 23 from 6 % in 2017-18 (Periodic Labour Force Surveys (PLFS) by NSO). Simultaneously, LFPR increased to 57.9 % in 2022- 23 from 49.8 % in 2017-18, driven by a surge in rural female LFPR.
- EPFO membership numbers grew by an impressive 11.3 % CAGR between FY14 and FY22, indicating increased salaried jobs.
- The share of regular-wage jobs declined from 22.8 % in FY18 to 20.9 % in FY23 but in absolute numbers jobs with a regular salary increased by almost 15 million between FY18 to FY23. Thus, a decline in the share of regular-wage jobs does not mean that the total number of jobs declined.
- Youth (age 15-29 years) employment has been rising in tandem with the youth population. Youth workforce participation rate increased from 31 % (2017-18) to 40.1 % (2022-23). This implies an additional 35 million youth have found work, even though the population of youth increased only by 17 million.

60. उत्तर बी

CAPEX पर सरकार का जोर, विशेष रूप से सड़क और राजमार्ग, रेलवे और आवास और शहरी मामलों जैसे बुनियादी ढांचे-गहन क्षेत्रों में, विकास के लिए दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह लंबे समय में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। अतः, कथन 1 सही है।
पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर ब्याज दर में कमी (निजी निवेश में भीड़) के कारण निजी निवेश को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर, क्राउडिंग आउट प्रभाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जब बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण निजी निवेश खर्च में कमी आती है, जिससे कुल निवेश खर्च की प्रारंभिक वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

पूंजीगत व्यय निजी उपभोग (सी), निवेश (आई), और सरकारी व्यय (जी) घटकों को बढ़ावा देकर समग्र मांग (एडी) को बढ़ावा देता है। (एडी = सी+आई+जी)। अतः, कथन 3 सही है।

61. उत्तर बी

बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2022-23 में 3.2% हो गई है (एनएसओ द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)। इसके साथ ही, ग्रामीण महिला एलएफपीआर में वृद्धि के कारण एलएफपीआर 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2022-23 में 57.9% हो गया।
FY14 और FY22 के बीच EPFO सदस्यता संख्या में प्रभावशाली 11.3% CAGR की वृद्धि हुई, जो वेतनभोगी नौकरियों में वृद्धि का संकेत है।
नियमित वेतन वाली नौकरियों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018 में 22.8% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 20.9% हो गई, लेकिन कुल संख्या में नियमित वेतन वाली नौकरियों में वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 23 के बीच लगभग 15 मिलियन की वृद्धि हुई। इस प्रकार, नियमित वेतन वाली नौकरियों की हिस्सेदारी में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि नौकरियों की कुल संख्या में गिरावट आई है।
युवा आबादी के साथ-साथ युवा (उम्र 15-29 वर्ष) रोजगार बढ़ रहा है। युवा कार्यबल भागीदारी दर 31% (2017-18) से बढ़कर 40.1% (2022-23) हो गई। इसका मतलब है कि अतिरिक्त 35 मिलियन युवाओं को काम मिल गया है, भले ही युवाओं की आबादी में केवल 17 मिलियन की वृद्धि हुई है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

62. Answer B

The IndiaAI Mission aims to set up AI computing infrastructure comprising more than 10,000 GPUs (Graphics Processing Units). So statement 1 is correct.

Priority will be given to selecting the most advanced GPUs for the computing infrastructure. So, statement 2 is correct.

The implementation of AI compute infrastructure will be carried out through a PPP model, with 50% viability gap funding provided by the government. So, statement 3 is not correct.

63. Answer A

- The investment climate in the country has transformed in recent years, leading to the emergence of 'investment' as a crucial driver of economic growth.
- The seemingly impressive investment rate in the first decade of the millennium was based on excessive borrowing and over-optimism, which eventually proved unsustainable.

64. Answer (c)

- Explanation Statement 1 is correct: The scheme focuses on improving the nutritional status and educational outcomes of school children.
- Statement 2 is incorrect: The Ministry of Women and Child Development is responsible for the implementation of the scheme.

65. Answer B

Despite strong global headwinds and tighter domestic monetary policy, if India is still expected to grow between 6.5 and 7.0%, and that too without the advantage of a base effect, it is a reflection of India's underlying economic resilience. Hence, statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

62. उत्तर बी

इंडियाएआई मिशन का लक्ष्य 10,000 से अधिक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) युक्त एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। अतः कथन 1 सही है।

कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के लिए सबसे उन्नत जीपीयू का चयन करने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो, कथन 2 सही है।

एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्यान्वयन पीपीपी मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा 50% व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान की जाएगी। अतः, कथन 3 सही नहीं है।

63. उत्तर a

हाल के वर्षों में देश में निवेश का माहौल बदल गया है, जिससे आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में 'निवेश' का उदय हुआ है।

सहस्राब्दी के पहले दशक में प्रतीत होने वाली प्रभावशाली निवेश दर अत्यधिक उधार लेने और अति-आशावाद पर आधारित थी, जो अंततः अस्थिर साबित हुई।

64. उत्तर c

• स्पष्टीकरण कथन 1 सही है: यह योजना स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति और शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है।

• कथन 2 गलत है: योजना के कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिम्मेदार है।

65. उत्तर b

मजबूत वैश्विक प्रतिकूलताओं और सख्त घरेलू मौद्रिक नीति के बावजूद, अगर भारत को अभी भी 6.5 और 7.0% के बीच बढ़ने की उम्मीद है, और वह भी आधार के लाभ के बिना प्रभाव, यह भारत की अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन का प्रतिबिंब है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

66. Answer D

- As per Indian Union Budget estimates for financial year 2023, direct tax revenue collections have been highly buoyant. Direct taxes accounted for 51.5% and indirect taxes accounted for 48.5% of total central tax collection in India. Hence, statement 1 is not correct.
- Advocates of direct taxation argue that it is a more equitable system, as it taxes individuals and corporations based on their income or wealth. Advocates of direct taxation argue that it is a more equitable system, as it taxes individuals and corporations based on their income or wealth. Indirect taxes are equal for any income level which makes them regressive. Hence, statement 2 is not correct.

67. Answer D

- Wholesale Price Inflation (WPI): WPI started to increase in 2022 with a peak value of 16.6% in May 2022 (as economic activities resumed post pandemic and the Russia-Ukraine conflict alleviated it more) and it slipped to 5.0% by year end. Hence, statement 1 is correct.
- Reasons for convergence: A cooling in WPI inflation of commodities such as crude oil, iron, aluminum etc. along with the rise in CPI inflation (fuelled by the rise in services cost). An important measure of demand-pull inflation - core inflation - remains sticky. Hence, statement 2 is correct.
- Even as inflation abated at the wholesale level, there has been a pass-through of previously high input costs onto retail prices, so CPI was on rise. Hence, statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations
RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

66. उत्तर डी

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारतीय केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार, प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह अत्यधिक उछाल वाला रहा है। भारत में कुल केंद्रीय कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 51.5% और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 48.5% है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

प्रत्यक्ष कराधान के समर्थकों का तर्क है कि यह एक अधिक न्यायसंगत प्रणाली है, क्योंकि यह व्यक्तियों और निगमों पर उनकी आय या संपत्ति के आधार पर कर लगाती है। प्रत्यक्ष कराधान के समर्थकों का तर्क है कि यह एक अधिक न्यायसंगत प्रणाली है, क्योंकि यह व्यक्तियों और निगमों पर उनकी आय या संपत्ति के आधार पर कर लगाती है। अप्रत्यक्ष कर किसी भी आय स्तर के लिए समान होते हैं जो उन्हें प्रतिगामी बनाता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

67. उत्तर डी

थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई): डब्ल्यूपीआई 2022 में मई 2022 में 16.6% के उच्चतम मूल्य के साथ बढ़ना शुरू हुआ (जैसे कि महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हुईं और रूस-यूक्रेन संघर्ष ने इसे और कम कर दिया) और साल के अंत तक यह 5.0% तक गिर गया। अतः, कथन 1 सही है।

अभिसरण के कारण: सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि (सेवा लागत में वृद्धि के कारण) के साथ-साथ कच्चे तेल, लोहा, एल्यूमीनियम आदि जैसी वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी। मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण उपाय - मुख्य मुद्रास्फीति - स्थिर बना हुआ है। अतः, कथन 2 सही है।

थोक स्तर पर मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद, पहले की उच्च इनपुट लागत का असर खुदरा कीमतों पर पड़ा है, इसलिए सीपीआई बढ़ रही थी। अतः, कथन 3 सही है।

68. Answer. C

Explanation

- The Indian Army has set up a 'quantum computing' laboratory and a center for 'artificial intelligence' in Mhow, Madhya Pradesh.
- This 'Quantum Computing Laboratory' has been established with the help of 'National Security Council Secretariat' (NSCS) to lead research and training in various key technology areas.
- The National Security Council is a three-tier organization that manages political, economic, energy and security issues of strategic concern.
- The Indian Army has also set up an 'Artificial Intelligence' (AI) center at the same institute.
- Quantum technology is based on the principles of quantum mechanics, which were developed in the early 20th century to describe the nature of atoms and elementary particles.

69. Answer c

Explanation

- Under this, out of 17 goals, 7 goals have been taken from the Millennium Development Goals, which have been adopted by making them more comprehensive. It came into force on January 1, 2016.
- Starting from the year 2015, in the 70th meeting of the United Nations General Assembly, sustainable development goals (SDGs) were set for the next 15 years.
- It is noteworthy that for the period of 2000-2015, a plan was made to achieve the Millennium Development Goals (MDG), whose time period was completed in the year 2015.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

68. उत्तर c

- भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में एक 'क्वांटम कंप्यूटिंग' प्रयोगशाला और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' के लिए एक केंद्र स्थापित किया है।
- यह 'क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला' विभिन्न प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय' (NSCS) की मदद से स्थापित की गई है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रि-स्तरीय संगठन है जो रणनीतिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों का प्रबंधन करता है।
- भारतीय सेना ने भी इसी संस्थान में एक 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (एआई) केंद्र स्थापित किया है।
- क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जो 20वीं सदी की शुरुआत में परमाणुओं और प्राथमिक कणों की प्रकृति का वर्णन करने के लिए विकसित किए गए थे।

69. उत्तर b

- इसके अंतर्गत 17 लक्ष्यों में से 7 लक्ष्यों को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से लिया गया है, जिन्हें और अधिक व्यापक बनाकर अपनाया गया है।
- यह 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ।
- वर्ष 2015 से शुरू होकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में, अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निर्धारित किए गए थे।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000-2015 की अवधि के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी, जिसकी समय अवधि वर्ष 2015 में पूरी कर ली गई थी।

70. Answer B

Explanation

- Securities with variable coupon rates, viz, Floating Rate Bonds, etc: The Security will carry a coupon rate which will vary according to the change in the Base Rate to which it is related. The description of the Base Rate and the manner in which the coupon rate is linked to the Base Rate will be announced in the Specific Notification. The coupon rate may be subject to a floor or cap if any, as the case may be. Hence, statement 1 is correct.
- Zero-Coupon Bonds: Zero-Coupon Bonds are issued at a discount and redeemed at par. No interest payment is made on such bonds at periodic intervals before maturity. On the basis of the bids received through tenders, the Reserve Bank of India will determine the cut-off price at which tenders for the purchase of Zero Coupon Bonds will be accepted at the auction. Hence, statement 2 is not correct.

Inflation-Indexed Bond (IIB) is a bond issued by the Sovereign (government), which provides the investor with a constant return irrespective of the level of inflation in the economy. Thus, Inflation-linked bonds are designed to protect investors from the adverse impact of inflation by linking the principal and interest payments of bonds to an inflation index such as the Wholesale Price Index (WPI) and the Consumer Price Index (CPI). The main objective of Inflation-Indexed Bonds is to provide a hedge and to safeguard the investor against macroeconomic risks in an economy. Hence statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

70. उत्तर B

व्याख्या।

- परिवर्ती कूपन दरों वाली प्रतिभूतियां, जैसे फ्लोटिंग रेट बांड, आदि: प्रतिभूति में निम्नलिखित कूपन दर जो आधार दर में परिवर्तन के अनुसार भिन्न होगी जिससे यह संबंधित है। आधार दर का विवरण और जिस तरीके से कूपन दर को आधार दर से जोड़ा जाता है, उसकी घोषणा विशिष्ट अधिसूचना में की जाएगी। कूपन दर किसी फ्लोर या कैप के अधीन हो सकती है, यदि कोई मामला हो सकता है। अतः कथन 1 सही है।
- जीरो-कूपन बांड: जीरो-कूपन बांड छूट पर जारी किए जाते हैं और सममूल्य पर भुनाए जाते हैं। परिपक्वता से पहले आवधिक अंतराल पर ऐसे बांडों पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। निविदाओं के माध्यम से प्राप्त बोलियों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक कट-ऑफ मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर निविदाएंजीरो कूपन बांड की खरीद के लिए नीलामी में स्वीकार किया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- इन्फ्लेशन-इंडेक्स्ड बॉन्ड (IIB) सॉवरेन (सरकार) द्वारा जारी किया गया एक बॉन्ड है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद निवेशक को निरंतर रिटर्न प्रदान करता है। इस प्रकार, मुद्रास्फीति से जुड़े बांडों को निवेशकों को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जैसे मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए बांड का मूलधन और ब्याज भुगतान। मुद्रास्फीति-अनुक्रमित बांड का मुख्य उद्देश्य हेजिंग प्रदान करना और एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक जोखिमों के खिलाफ निवेशक की सुरक्षा करना है। इस तरह कथन 3 सही है।

71. Answer C

Explanation

- The Food and Agriculture Organization is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. Its Latin motto, fiat panis, translates to "let there be bread". Hence, statement 1 is correct.
- The FAO Food Price Index (FFPI) is a measure of the monthly change in international prices of a basket of food commodities. It consists of the average of five commodities (cereals, oilseeds, dairy products, meat, and sugar) group price indices weighted by the average export shares of each of the groups over 2014-2016. Hence, statement 2 is correct.
- FAO's Desert Locust Information Service (DLIS) produces monthly Desert Locust Bulletins that are distributed by email to affected countries, donors, and other relevant agencies and individuals. During periods of increased locust activity, bulletins are supplemented with alerts and updates. The FAO also brings out a number of publications/reports, some of which are,

o the State of the World,
o the Global Report on Food Crises,
o the State of Food and Agriculture,
o the State of the World's Forests. Hence, statement 3 is correct.

72. Answer B

Explanation

- The National Action Plan has been framed for the entire population of equids reared in different management and animal husbandry practices in India.

• Glanders caused by B. mallei, is a notifiable disease in India since 1899, by an Act of Parliament. The disease has been occurring sporadically in a few states but surveillance of the disease during the last decade revealed that B.mallei infection has spread to a few more states due to the movement of asymptomatic carrier equids.
• Glanders is a contagious and fatal disease of equines, viz., horses, donkeys, and mules, caused by infection with the bacterium Burkholderia mallei (B. mallei). Hence statement 1 is correct.
• Humans can also get this disease. Hence statement 2 is not correct.
• No vaccine is available for the disease. Hence statement 3 is correct.

71. उत्तर C

व्याख्या।

- खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य, fiat panis, "लेट देयर बी ब्रेड" का अनुवाद करता है। अतः कथन 1 सही है।
- एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक उपाय है। इसमें 2014-2016 के दौरान प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेयरों द्वारा भारित पांच वस्तुओं (अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी) समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है। अतः कथन 2 सही है।

72. उत्तर B

व्याख्या

- भारत में विभिन्न प्रबंधन और पशुपालन प्रथाओं में पाले गए समानों की पूरी आबादी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है।
- संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी. मल्लेई के कारण ग्लैंडर्स, भारत में 1899 से एक सूचनात्मक बीमारी है। यह रोग छिटपुट रूप से कुछ राज्यों में हो रहा है लेकिन पिछले दशक के दौरान रोग की निगरानी से पता चला है कि स्पर्शोन्मुख वाहक समानों के संचलन के कारण बी.मेली संक्रमण कुछ और राज्यों में फैल गया है।
- ग्लैंडर्स घोड़ों, घोड़ों, गधों और खच्चरों की एक संक्रामक और घातक बीमारी है, जो बुर्कहोल्डरिया मैलेली (बी. मैलेली) जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। अतः कथन 1 सही है।
- मनुष्य को भी यह रोग हो सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- रोग के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अतः कथन 3 सही है।

73. Answer A

Explanation

- Paramparagat Krishi Vikas Yojana, launched in 2015 is an elaborated component of Soil Health Management (SHM) of the major project National Mission of Sustainable Agriculture (NMSA). Under PKVY Organic farming is promoted through the adoption of the organic village by cluster approach and PGS (Participatory Guarantee Systems) certification. Hence statement 1 is correct.

• Under PKVY, farmers are provided financial assistance of Rs 50,000 per hectare/ 3 years, out of which Rs. 31,000 (62%) is provided directly through DBT for inputs (bio-fertilizers, bio-pesticides, organic manure, compost, vermicompost, botanical extracts, etc). Hence statement 2 is not correct.

• The funding pattern under the scheme is in the ratio of 60:40 by the Central and State Governments respectively. In the case of North Eastern and the Himalayan States, Central Assistance is provided in the ratio of 90:10 (Centre: State) and for Union Territories, the assistance is 100%.

• At least 30% of the budget allocations need to be earmarked for women beneficiaries/farmers as part of efforts to bring them into mainstream agriculture. Hence statement 3 is not correct.

• In addition, organic farming is also supported under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), and National Project on Organic Farming (NPOF), Network Project on Organic Farming under the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).

73. उत्तर ए

व्याख्या

- परम्परागत कृषि विकास योजना, 2015 में शुरू की गई प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है।
- पीकेवीवाई के तहत क्लस्टर द्वारा जैविक गांव को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता हैदृष्टिकोण और पीजीएस (भागीदारी गारंटी प्रणाली) प्रमाणन। अतः कथन 1 सही है।
- पीकेवीवाई के तहत, किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से रु. 31,000 (62%) इनपुट (जैव-उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, जैविक खाद, खाद, वर्मीकम्पोस्ट, वनस्पति अर्क, आदि) के लिए सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के तहत वित्त पोषण पैटर्न क्रमशः 60:40 के अनुपात में है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के मामले में, केंद्रीय सहायता 90:10 (केंद्र: राज्य) के अनुपात में प्रदान की जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सहायता 100% है।
- बजट आवंटन का कम से कम 30% महिला लाभार्थियों/किसानों को कृषि की मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के तहत निर्धारित करने की आवश्यकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
- इसके अलावा, जैविक खेती को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), और जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीओएफ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना के तहत भी समर्थन दिया जाता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

74. Answer A

Explanation

• Recently, many existing schemes of the Ministry of Tribal Affairs have been merged, revamped and the scope has been widened. The 3 schemes meant for the comprehensive development of tribals are asunder.

- Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojna
- Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission
- Venture Capital Fund for STs
- Venture Capital Fund for STs:
- An initial corpus of 50 crores has been sanctioned for the scheme of 'Venture Capital Fund for Scheduled Tribes' (VCF-ST), which is aimed at promoting Entrepreneurship among the STs.

Hence, statement 1 is not correct.

- The VCF-ST scheme would be a social sector initiative to promote ST entrepreneurship and to support and incubate the start-up ideas of ST youth. Hence, statement 2 is correct.
- Currently, the scheme is limited only to Scheduled Tribes.
- National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) is the central nodal implementing agency for this scheme. Hence, statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

74. उत्तर A

व्याख्या।

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कई मौजूदा योजनाओं को विलय कर दिया गया है, और नया रूप दिया गया है और इसका दायरा बढ़ाया गया है। आदिवासियों के व्यापक विकास के लिए बनाई गई 3 योजनाएं इस प्रकार हैं।
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
- एसटी के लिए वेंचर कैपिटल फंड
- एसटी के लिए वेंचर कैपिटल फंड:
- 'अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड' (वीसीएफ-एसटी) की योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष स्वीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य एसटी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

अतः कथन 1 सही नहीं है।

- वीसीएफ-एसटी योजना एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने और एसटी युवाओं के स्टार्ट-अप विचारों को समर्थन देने और विकसित करने के लिए एक सामाजिक क्षेत्र की पहल होगी। अतः कथन 2 सही है।
- वर्तमान में यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) इस योजना के लिए केंद्रीय नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

75. Answer B

Explanation

- Union Budget 2022 highlighted that, 2023 has been announced as the International Year of Millets and in In turn, support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally.
- India produces all the nine commonly known millets and is the largest producer and second-largest exporter of millets globally. The Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW) is implementing a Sub-Mission on Nutri-Cereals (Millets) under National Food Security Mission (NFSM) to enhance the area, production & productivity of millets including bajra. Through the efforts made by the Government, the production of millets has increased from 14.52 million tonnes in 2015-16 to 17.96 million tonnes in 2020-21. Hence, statement 1 is correct.
- In view of the nutritional value of the millets, the Government has notified millets as Nutri-cereals in April 2018. Millets are also increasingly finding favor among farmers for being climate-friendly crops that are drought resistant, growing in infertile soil. Hence, statement 2 is correct.
- The Millets are a rich source of Protein, Fibre, Minerals, Iron, and Calcium. They are gluten-free with a low glycemic index which constitutes good food for people suffering from diabetes. It had also been found that millets were anti-carcinogenic foods and anti-hypertensive and they help prevent obesity and heart diseases. Hence, statement 3 is not correct.

76. Answer B

Explanation

- PM e-VIDYA: Launched in 2020, PM e-Vidya unifies all efforts related to digital/online/on-air education to enable coherent multi-mode access to education. Hence option (b) is the correct answer.

75. उत्तर बी

- व्याख्या केंद्रीय बजट 2022 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि, 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है बदले में, कटाई के बाद के मूल्यवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- भारत सभी नौ सामान्य रूप से ज्ञात बाजरा का उत्पादन करता है और विश्व स्तर पर बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत न्यूट्री-अनाज (बाजरा) पर एक उप-मिशन लागू कर रहा है।
- बाजरा सहित बाजरा के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। सरकार के प्रयासों से बाजरा का उत्पादन 2015-16 के 14.52 मिलियन टन से बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है। 2020-21 में मिलियन टन। अतः कथन 1 सही है।
- बाजरा के पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरा को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया है। बाजरा भी किसानों के बीच जलवायु-अनुकूल फसल होने के कारण तेजी से बढ़ रही है, जो सूखा प्रतिरोधी है, बंजर मिट्टी में बढ़ रही है। अतः कथन 2 सही है।
- बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। वे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ लस मुक्त हैं जो मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए अच्छा भोजन है। यह भी पाया गया कि बाजरा एंटी-कार्सिनोजेनिक खाद्य पदार्थ और एंटी-हाइपरटेंसिव थे और वे मोटापे और हृदय रोगों को रोकने में मदद करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

76. उत्तर बी

व्याख्या

- पीएम ई-विद्या: 2020 में लॉन्च किया गया, पीएम ई-विद्या शिक्षा के सुसंगत मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल / ऑनलाइन / ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। इसलिए विकल्प (बी) सही उत्तर है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

77. Answer B

Explanation

- National Mission on Cultural Mapping (NMCM), an initiative of the Ministry of Culture under the umbrella scheme of 'Kala Sanskriti Vikas Yojana' intends to collect and present a Nationwide Directory/Database of Artists in the Visual, Performing and Literary Arts. Hence statement 1 is correct and statement 2 is not correct.
- The Mission encompasses data mapping, demography building, formalizing the processes and bringing all cultural activities under one umbrella for better results.
- National Cultural WorkPlace (NCWP):
- The NCWP shall be a fully equipped cultural portal that will serve as a common interaction workplace for all stakeholders including artists, institutions, NGOs and the Ministry of Culture.
- A 'National Cultural workplace' is also planned as a virtual portal for artists to interact, evolve & learn. Hence statement 3 is correct.

78. Answer B

• NISHTHA - National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement is an initiative to build the capacities of both the teachers and the school principals at the elementary stage. Hence statement 1 is correct.

• The initiative is an Integrated Teacher Training Programme of the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education and is a part of the National Mission to improve learning outcomes at the Elementary level under the Centrally Sponsored Scheme of Samagra Shiksha initiative. Hence statement 2 is correct.

• NISHTHA in face-to-face mode training was launched in 2019, due to the COVID-19 pandemic situation it was converted into an online mode and conducted through DIKSHA and NISHTHA portals of the NCERT. Hence statement 3 is not correct.

77. उत्तर B

व्याख्या

- सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन (NMCM), 'कला संस्कृति विकास योजना' की छतरी योजना के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दृश्य, प्रदर्शन और साहित्य कला में कलाकारों की एक राष्ट्रव्यापी निर्देशिका/डेटाबेस एकत्र करना और प्रस्तुत करना है। अतः कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है।
- मिशन में डेटा मैपिंग, जनसांख्यिकी निर्माण, प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाना और बेहतर परिणामों के लिए सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक छतरी के नीचे लाना शामिल है।
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य स्थल (NCWP): एनसीडब्ल्यूपी पूरी तरह से सुसज्जित सांस्कृतिक पोर्टल होगा जो कलाकारों, संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और संस्कृति मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के लिए एक आम बातचीत कार्यस्थल के रूप में काम करेगा।
- कलाकारों के साथ बातचीत करने, विकसित होने और सीखने के लिए वर्चुअल पोर्टल के रूप में एक 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल' की भी योजना बनाई गई है। अतः कथन 3 सही है।

78. उत्तर B

निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों दोनों की क्षमता का निर्माण करने की एक पहल है। अवस्था। अतः कथन 1 सही है।

- यह पहल शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और समग्र शिक्षा पहल की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है। अतः कथन 2 सही है।
- निष्ठा को फेस-टू-फेस मोड प्रशिक्षण 2019 में शुरू किया गया था, COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण इसे ऑनलाइन मोड में परिवर्तित किया गया और दीक्षा और निष्ठा के माध्यम से आयोजित किया गया एनसीईआरटी के पोर्टल। अतः कथन 3 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

79. Answer D

Explanation

- BharatNet is a flagship mission implemented by Bharat Broadband Network Limited (BBNL) wherein the Government of India through the Department of Telecom had created a strategic plan for providing broadband connectivity to 2,50,000 gram panchayats in India on optical fiber cable with a minimum of 100 Mbps speed. Hence statement 1 is not correct.
- Service providers may also utilize the dark fiber on the new cable laid by BBNL between the block and Gram Panchayats called incremental cable, for extending its services to Gram Panchayats. The dark fiber is available from the Fiber Point of Interconnect (with the existing fiber) to the Gram Panchayats.Hence statement 2 is not correct.

80. Answer B

Sergeant Plan of Education (1944):

o It was worked out by the Central Advisory Board of Education in 1944.

o It recommended:

- Universal free and compulsory education for children between the ages of 6 and 11. Hence option (b) is the correct answer.
- A school course of six years for children between the ages of 11 and 17.

81. Answer C

- Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune is the main body responsible for the execution and coordination of the mission. Hence statement 2 is correct.
- The overall objective of NMM is to improve the monsoon prediction over India on all time scales and hence it is implemented for the whole country which includes all the States and UTs. Hence statement 1 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

79. उत्तर डी

व्याख्या

- BharatNet भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है जिसमें भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत में 2,50,000 ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 100 ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई थी। एमबीपीएस स्पीड। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- सेवा प्रदाता ग्राम पंचायतों को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के बीच बीबीएनएल द्वारा बिछाई गई नई केबल पर डार्क फाइबर का उपयोग कर सकते हैं, जिसे इंक्रीमेंटल केबल कहा जाता है। डार्क फाइबर फाइबर प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्ट (मौजूदा फाइबर के साथ) से ग्राम तक उपलब्ध है पंचायत। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।

80. उत्तर बी

शिक्षा की सार्जेंट योजना (1944):

o इसे 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था।

o इसकी अनुशंसा की गई:

6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसलिए विकल्प (बी) सही उत्तर है।

11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए छह साल का स्कूल पाठ्यक्रम।

81. उत्तर सी

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे मिशन के निष्पादन और समन्वय के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है। अतः कथन 2 सही है।

एनएमएम का समग्र उद्देश्य सभी समय के पैमाने पर भारत में मानसून की भविष्यवाणी में सुधार करना है और इसलिए इसे पूरे देश के लिए लागू किया गया है जिसमें सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।

82. Answer B

- The constitution of the National Company Law Tribunal (NCLT) and National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) was done in 2016 under the companies Act, 2013. These bodies have been constituted for faster resolution of corporate disputes and to reduce the multiplicity of agencies thereby promoting 'ease of doing business' in the country. Hence statement 1 is correct.
- NCLAT hears appeals against the orders of National Company Law Tribunal(s) (NCLT). It is also the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by Insolvency and Bankruptcy Board of India. The Competition Appellate Tribunal under the provisions of Competition Act was dissolved in 2017 and merged with NCLAT. The appeal against the orders of Competition Commission of India is now with NCLAT. Hence statement 2 is not correct and statement 3 is correct.

83. Answer C

- Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT) outlets provide drugs for cancer and cardiovascular diseases along with cardiac implants at a 60 to 90 percent discount on prevailing market rates. Hence option (c) is correct.

84. Answer A

- The Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) was launched in 1993.
- Initially, the Ministry of Rural Development was the nodal ministry for this scheme. In October 1994, this scheme was transferred to the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Hence, statement 1 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

82. उत्तर बी

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन 2016 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया था। इन निकायों का गठन कॉर्पोरेट विवादों के तेजी से समाधान और एजेंसियों की बहुलता को कम करने के लिए किया गया है। देश में 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा देना। अतः कथन 1 सही है।

एनसीएलएटी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है। यह भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को 2017 में भंग कर दिया गया और एनसीएलएटी में विलय कर दिया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील अब एनसीएलएटी के पास है। अतः कथन 2 सही नहीं है और कथन 3 सही है।

83. उत्तर सी

उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी) आउटलेट मौजूदा बाजार दरों पर 60 से 90 प्रतिशत की छूट पर हृदय प्रत्यारोपण के साथ-साथ कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाएं प्रदान करते हैं। अतः विकल्प (सी) सही है।

84. उत्तर ए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) 1993 में शुरू की गई थी।

प्रारंभ में, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय था। अक्टूबर 1994 में इस योजना को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

85. Answer C

- One Nation One Ration Card (ONORC) scheme is aimed at enabling migrant workers and their family members to buy subsidized rations from any fair price shop anywhere in the country under the National Food Security Act, 2013. Hence statement 1 is correct.
- As many as 81 crore people will be benefited from this scheme because they will receive wheat at Rs 2 per kg and rice at Rs 3 per kg. A migrant will be allowed to buy a maximum of 50 percent of the family quota. This is to ensure that the individual, after shifting to another place, does not buy the entire family quota in one go. Hence statement 3 is correct.
- While Aadhaar linkage is not necessary to access NFSA benefits in a beneficiary's local registered ration shop, located closest to her home address, it will be necessary to access the portability scheme. The beneficiaries would be able to avail of the entitled foodgrains after biometric/Aadhaar authentication on ePoS (electronic Point of Sale) devices. Hence statement 2 is correct.

86. Answer : d

Sulthan Bathery – It is a municipal town in Wayanad, Kerala.

Temple – Sulthan Bathery has a stone temple that was once known as Ganapathyvattam.

The temple, built in the prevalent architectural style of the Vijayanagar dynasty, was constructed by Jains who migrated to Wayanad from areas in present-day Tamil Nadu and Karnataka in the 13th century.

Tipu Sultan – The temple was partly destroyed by Tipu Sultan.

Between 1750 and 1790, today's northern Kerala was invaded several times by the rulers of Mysuru, Hyder Ali and his son Tipu.

Tipu Sultan used the Maha Ganapathy temple in Sulthan Bathery as a battery or store for weapons for his army in the Malabar region (today's North Kerala, including Wayanad).

This led to the British recording Ganapathyvattam as Tipu Sultan's Battery, and the name survived as Sulthan Bathery.

85. उत्तर सी

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाला राशन खरीदने में सक्षम बनाना है। इसलिए कथन 1 सही है।

इस योजना से 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलेगा। एक प्रवासी को पारिवारिक कोटे का अधिकतम 50 प्रतिशत खरीदने की अनुमति होगी। यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने के बाद, एक ही बार में पूरे परिवार का कोटा नहीं खरीद ले। अतः कथन 3 सही है।

जबकि लाभार्थी के घर के पते के निकटतम स्थित स्थानीय पंजीकृत राशन की दुकान में एनएफएसए लाभों तक पहुंचने के लिए आधार लिंक आवश्यक नहीं है, पोर्टेबिलिटी योजना तक पहुंचने के लिए आधार लिंक करना आवश्यक होगा। लाभार्थी ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद हकदार खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे। अतः कथन 2 सही है।

86. उत्तर: डी

सुल्तान बाथरी - यह केरल के वायनाड में एक नगरपालिका शहर है।

मंदिर - सुल्तान बाथरी में एक पत्थर का मंदिर है जिसे कभी गणपतिवट्टम के नाम से जाना जाता था।

विजयनगर राजवंश की प्रचलित स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों से वायनाड में आए जैनियों द्वारा किया गया था।

टीपू सुल्तान - मंदिर को टीपू सुल्तान ने आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था।

1750 और 1790 के बीच, आज के उत्तरी केरल पर मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू ने कई बार आक्रमण किया।

टीपू सुल्तान ने मालाबार क्षेत्र (आज का उत्तरी केरल, वायनाड सहित) में अपनी सेना के लिए सुल्तान बाथरी में महा गणपति मंदिर का उपयोग बैटरी या हथियारों के भंडार के रूप में किया था।

इसके चलते ब्रिटिशों ने गणपतिवट्टम को टीपू सुल्तान की बैटरी के रूप में दर्ज किया और इसका नाम सुल्तान बाथरी रह गया।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

87. Answer b

The Unique Identification Authority of India puts in place a resident-friendly facility to help residents update address in Aadhaar online with the consent of the Head of Family.

The Aadhaar Act has been notified conferring legal status upon the Unique Identification Authority of India (UIDAI) to issue Aadhaar to residents of India including children below five years.

88. Answer A

- It was set up by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010.
- GCF is mandated to invest 50% of its resources to mitigation and 50% to adaptation in grant equivalent.
- GCF has a crucial role in serving the Paris Agreement, supporting the goal of keeping average global temperature rise well below 2 degrees C. It does this by channeling climate finance to developing countries, which have joined other nations in committing to climate action.

89. Answer: B

Explanation:

- Statement 1 is correct. Rashtriya Vigyan Puraskar (RVP) awards will no longer include cash prizes but will instead offer a certificate and medallion to the awardees.
- Statement 2 is correct. Vigyan Ratna awards are designed to honor individuals for their lifetime contributions along with excellence in any field of science.
- Statement 3 is incorrect. While PIOs are eligible for some of the awards, there are specific quotas and restrictions. Not all awards are open to PIOs. For example, PIOs can be eligible for Vigyan Shri and Vigyan Yuva-Shanti Swarup Bhatnagar awards, but they are not eligible for the Vigyan Team awards.
- Statement 4 is incorrect. While there is no age limit for most of the awards, there is an age limit specified for one of the awards, which is the Vigyan Yuva-Shanti Swarup Bhatnagar awards. Recipients of this award must be 45 years or younger.

General Studies RACE IAS Rajesh Academy for Civil Examinations

87. सही विकल्प: (बी)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने परिवार के मुखिया की सहमति से निवासियों को आधार में पता ऑनलाइन अपडेट करने में मदद करने के लिए एक निवासी-अनुकूल सुविधा शुरू की है।

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित भारत के निवासियों को आधार जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को कानूनी दर्जा प्रदान करते हुए आधार अधिनियम को अधिसूचित किया गया है।

88. उत्तर ए

इसकी स्थापना 2010 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) द्वारा की गई थी।

जीसीएफ को अपने संसाधनों का 50% शमन के लिए और 50% अनुदान समकक्ष में अनुकूलन के लिए निवेश करने के लिए अनिवार्य है।

पेरिस समझौते को पूरा करने में जीसीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लक्ष्य का समर्थन करता है। यह विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करके ऐसा करता है, जो जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध अन्य देशों में शामिल हो गए हैं।

89. उत्तर: बी

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (आरवीपी) पुरस्कारों में अब नकद पुरस्कार शामिल नहीं होंगे, बल्कि पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया जाएगा।

कथन 2 सही है. विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ-साथ व्यक्तियों को उनके जीवनकाल के योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

कथन 3 ग़लत है. हालाँकि पीआईओ कुछ पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, लेकिन विशिष्ट कोटा और प्रतिबंध भी हैं। सभी पुरस्कार पीआईओ के लिए खुले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पीआईओ विज्ञान श्री और विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन वे विज्ञान टीम पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

कथन 4 गलत है. जबकि अधिकांश पुरस्कारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, एक पुरस्कार के लिए एक आयु सीमा निर्दिष्ट है, जो विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता की आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।

90. Answer A

Project tiger is a centrally sponsored scheme. The largest tiger reserve in India is Nagarjunsagar, commonly known as Srisailam, in Andhra Pradesh. Tiger Census is carried out every 4 years in India by NTCA. Guru Ghasi Das tiger reserve is in Chhattisgarh.

91. Answer C

- Recently, India has been handed over the presidency Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) for 2022-23 by the outgoing Council Chair, France in its 3rd Annual Summit in Japan. It was launched in June, 2020, with fifteen members.
- The Global Partnership in Artificial Intelligence is described as the 'fruition of an idea developed within the G7. It is a multi-stakeholder initiative on artificial intelligence (AI), which aims to fill what it describes as 'the gap between theory and practice on Al, by supporting cutting-edge research, as well as applied activities, on Al-related priorities.
- There are 29 members as of now.

92. Answer B

- Statement 1 is correct: The governor is empowered to direct that an act of Parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modifications and exceptions.
- Statement 2 is not correct: The Governor of Assam may likewise direct that an Act of Parliament does not apply to a tribal area (autonomous district) in the state or apply with specified modifications and exceptions. The President enjoys the same power with respect to tribal areas (autonomous districts) in Meghalaya, Tripura and Mizoram.
- Statement 3 is correct: The President can make regulations for the peace, progress and good government of the five Union Territories– the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh. A regulation so made has the same force and effect as an act of Parliament. It may also repeal or amend any act of Parliament in relation to these union territories.

90. उत्तर a

प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर है, जिसे आमतौर पर श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है। भारत में हर 4 साल में एनटीसीए द्वारा बाघों की गणना की जाती है। गुरु घासी दास बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है।

91. उत्तर सी

हाल ही में, भारत को जापान में अपने तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में फ्रांस के निवर्तमान परिषद अध्यक्ष द्वारा 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएआई) की अध्यक्षता सौंपी गई है। इसे जून, 2020 में पंद्रह सदस्यों के साथ लॉन्च किया गया था।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक साझेदारी को 'जी7 के भीतर विकसित एक विचार का फल' के रूप में वर्णित किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर एक बहु-हितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य अल-संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान के साथ-साथ व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके, 'अल पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर' को भरना है।

92. उत्तर बी

कथन 1 सही है: राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू नहीं होता है।

कथन 2 सही नहीं है: असम के राज्यपाल इसी तरह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य के आदिवासी क्षेत्र (स्वायत्त जिले) पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू नहीं होता है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों) के संबंध में राष्ट्रपति को समान शक्ति प्राप्त है।

कथन 3 सही है: राष्ट्रपति पाँच केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लद्दाख की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। इस प्रकार बनाए गए विनियम का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। यह इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकता है।

93. Answer B

- ATMs set up, owned and operated by non-banks are called WLAs. Non-bank ATM operators are authorised under the Payment & Settlement Systems Act, 2007 by the RBI.
- WLA operators can buy wholesale cash directly from the Reserve Bank and currency chests. They can also source cash from any scheduled bank, including Cooperative Banks and Regional Rural Banks.

94. Answer:B

- The Psyche mission is a journey to a unique metal asteroid orbiting the Sun between Mars and Jupiter.
- What makes the asteroid Psyche unique is that it appears to be the exposed nickel-iron core of an early planet, one of the building blocks of our solar system.
- The mission is led by Arizona State University. NASA's Jet Propulsion Laboratory is responsible for mission management, operations and navigation.

95. Answer B

- "The PM CARES Fund is not a public authority under the ambit of section 2(h) of the RTI Act, 2005," the PMO said in response to the RTI application. Hence, statement 2 is not correct.

96. Answer C

The Global Hunger Index 2023, India ranked 111th out of 125 countries, indicating a serious level of hunger.

The index is jointly released by Concern Worldwide and Welthungerhilfe every October.

The Hunger Index measures countries' performance on four component indicators: undernourishment, child wasting, child stunting and child mortality.

The GHI is a tool designed to comprehensively measure and track hunger at global, regional, and national levels, reflecting multiple dimensions of hunger over time.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

93. उत्तर बी

गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित एटीएम को डब्ल्यूएलए कहा जाता है। गैर-बैंक एटीएम ऑपरेटर आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत हैं।

WLA संचालक सीधे रिज़र्व बैंक और मुद्रा चेस्ट से थोक नकदी खरीद सकते हैं। वे सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित किसी भी अनुसूचित बैंक से भी नकदी प्राप्त कर सकते हैं।

94. उत्तर:बी

साइकी मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय धातु क्षुद्रग्रह की यात्रा है।

जो बात क्षुद्रग्रह साइकी को अद्वितीय बनाती है वह यह है कि यह एक प्रारंभिक ग्रह का खुला निकेल-आयरन कोर प्रतीत होता है, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण खंडों में से एक है।

इस मिशन का नेतृत्व एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला मिशन प्रबंधन, संचालन और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है।

95. उत्तर बी

आरटीआई आवेदन के जवाब में पीएमओ ने कहा, "पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।" इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

96. उत्तर सी

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जो भूख के गंभीर स्तर का संकेत देता है।

यह सूचकांक हर अक्टूबर में कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ़ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।

भूख सूचकांक चार घटक संकेतकों पर देशों के प्रदर्शन को मापता है: अल्पपोषण, बाल विकास, बाल विकास और बाल मृत्यु दर।

जीएचआई एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है।

97. Answer: B

- One Future Alliance' (OFA) is a voluntary initiative proposed by the G20 India Presidency with support from UNDP and its knowledge partners.
- It aims to unite governments, the private sector, academia, donor agencies, civil society, and other stakeholders to enhance global efforts in the DPI ecosystem.
- Digital public infrastructure (DPI) is a shared means to many ends. It is a critical enabler of digital transformation and is helping to improve public service delivery at scale.

98. Answer: B

Malaviya Mission aims to provide tailored training programmes for teachers and to improve the capacity building of faculty members in higher educational institutions.

The capacity building under the Mission will be mapped to the credit framework to ensure career progression pathways for educators.

99. Answer B

The foreign contribution received must be used only for the purpose for which it was obtained, and no more than 20% of the foreign contribution received in a fiscal year may be used to cover administrative costs. Statement 2 is incorrect.

100. Answer B

China, the US, and India, who collectively account for about 42% of global greenhouse gas emissions and are the top three emitters in that order, were all absent from the CAS. Statement 2 is not correct

97. उत्तर: बी

वन फ्यूचर अलायंस' (ओएफए) यूएनडीपी और उसके ज्ञान भागीदारों के समर्थन से जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है।

इसका उद्देश्य डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, दाता एजेंसियों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को एकजुट करना है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) कई उद्देश्यों के लिए एक साझा साधन है। यह डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है

98. उत्तर: बी

मालवीय मिशन का उद्देश्य शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना और उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण में सुधार करना है।

शिक्षकों के लिए करियर में प्रगति के रास्ते सुनिश्चित करने के लिए मिशन के तहत क्षमता निर्माण को क्रेडिट ढांचे में मैप किया जाएगा।

99. उत्तर बी

प्राप्त विदेशी योगदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था, और एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त विदेशी योगदान का 20% से अधिक का उपयोग प्रशासनिक लागतों को कवर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कथन 2 गलत है.

100. उत्तर बी

चीन, अमेरिका और भारत, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 42% हिस्सा हैं और उस क्रम में शीर्ष तीन उत्सर्जक हैं, सभी सीएएस से अनुपस्थित थे। कथन 2 सही नहीं है

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations